1	2	3	4	5
24	नागालैण्ड	426	21	128
25	उड़ीसा	12393	620	3730
26	पांडिचेरी	305*†	15.2	64
27	कैरीकल	73	3.7	18
28	माह	15	0.7	4
29	यनम	7	0.4	2
30	पंजाब	7945	397	2392
31	राजस्थान	16914	846	5092
32	सिक्किम	165	8	50
33	तमिलनाडु	22547	1127	6790
34	त्रिपुरा	1001	50	302
35	उत्तर प्रदेश	52926	2646	15936
36	पश्चिमी बंगाल	25888	1294	7796
	योग	334520	16654	99950

*इसमें मई, 1990 से आगे दिल्ली के कोटे में की गई 1032 टन की वृद्धि तथा पांडिचेरी के कोटे में 108 टन की वृद्धि शामिल है।

**इसमें जुलाई, 1993 से बढ़ाई गई 1200 टन की मात्रा शामिल है।

†फरवरी, 1994 से बढ़ाई गई 252 टन की मात्रा शामिल है ।

Sugar Factories in A.P.

1606. DR. YELAMANCHILI SIVAJI :

Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) how many applications seeking letters of intent to locate sugar factories in Andhra Pradesh are pending;

(b) since how long they are pending;

(c) how many of them are recommended by the State Government; and

(d) what are the reasons for the abnormal delay in clearing them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI) : (a) to (d) 97 applications have been received, as on 31-12-1993, from Andhra Pradesh through the Department of Industrial Development for setting up of new sugar factories in that State. Out of these, 71 applications were recommended by the State Government. All applications have been Scrutinised by the Screening Committee in the Ministry of Food. After examination, recommendations of the Ministry of Food have been sent to the Ministry of Industry where these have been considered by the Licensing Committee. The letters of intent would be issued by the Ministry of Industry.

महाराष्ट्र में चीनी मिलें स्थापित किए जाने का प्रस्ताव

1607. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलें स्थापित करने के राज्य-वार कितने-कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे कितने प्रस्ताव भेजे हैं तथा इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी;

(ग) क्या सरकार सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत चीनी मिलें स्थापित करने हेतु ऋण देती है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है, और

(ङ) क्या सावधिक ऋण देने वाली संस्थाएं भी इस संबंध में चीनी मिलों की सहायता करेंगी ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) 31-1-1994 तक सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलों की स्थापना के के लिए विचारार्थ लंबित आवेदनों की राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है :—

1. महाराष्ट्र	231
2. बिहार	2
3. कर्नाटक	8
4. उत्तर प्रदेश	1
कुल :	242

(ख) 31-1-1994 तक की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से 231 आवेदन प्राप्त हुए हैं इनमें से 225 आवेदनों की जांच समिति द्वारा जांच कर ली गई है । जांच के बाद खाद्य मंत्रालय की सिफारिशें लाइसेंस समिति द्वारा विचार के लिए उद्योग मंत्रालय को भेज दी गई हैं जिसके बाद उस मंत्रालय द्वारा आशय-पत्र जारी किए जाएंगें । शेष 6 आवेदनों पर कारवाई की जा रही है ।

(ग) और (घ) सरकार सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलें लगाने के लिए कोई ऋण उपलब्ध नहीं कराती है । तथापि, ऐसे ऋण वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपक्रमों को सीधे उपलब्ध कराए जाते हैं ।

(ङ) वित्तीय संस्थाओं ने सूचित किया है सहकारी क्षेत्र में चीनी इकाइयों के अवधि ऋणों के आवेदनों पर तभी विचार किया जाएगा जब संबंधित राज्य सरकारें वर्तमान सहकारी चीनी तथा वस्त्र इकाइयों द्वारा ऋणों की वापसी में की गई चूक, जिनके ऋणों की राज्य सरकारों द्वारा गारंटी दी गई थी, को क्लीयर कर दें ।

Increase in Prices of Foodgrains

1608. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN : Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) whether the prices of food grains hiked in the wake of Budget would be reconsidered and brought to normal;

(b) what steps the Minister is contemplating to bring down this spiralling foodgrains prices;

(c) what is the reason for this price hike of food grains;

(d) whether the Minister is aware of the election promises that prices will be rolled down to that of 1987; and

(e) if so, what stringent measures the food Minister intends to take to reduce the hike prices of food grains ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI) : (a) to (c) To partially absorb the increase in the procurement prices of wheat and paddy paid to farmers during 1993-94 and consequential increase in their procurement cost, the Central Issue Prices (ex-FCI godown) of wheat and rice issued to the States/Union Territories by Food Corporation of India from the central pool for the public distribution